एयरएशिया इंडिया से एग्जिट कर सकती है टाटा संस

मुंबई 16 नवम्बर (ए)। टाटा संस मुश्किलों का सामना कर रही एयरएशिया इंडिया से एग्जिट करने पर विचार कर रही है। मामले की जानकारी रखने वाले कई सूत्रों ने बताया कि टाटा संस केवल एक एयरलाइन बिजनेस यानी विस्तारा पर ध्यान देना चाहती है, जो सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इसकी जॉइंट वेंचर है। इस संबंध में बातचीत शुरू हो गई है। उधर टाटा ग्रुप देश की दूसरे नंबर की एयरलाइन जेट एयरवेज का मालिकाना हक इसके फाउंडर नरेश गोयल से खरीदने के करीब पहुंचती दिख रही है। एक सूत्र ने बताया कि टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस ने एयरएशिया इंडिया से एग्जिट करने और इंडिया में इकलौती फुल सर्विस प्राइवेट एयरलाइन यानी विस्तारा प्लस जेट को चलाने का प्रस्ताव रखा है। एयरएशिया इंडिया में टाटा संस की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बाकी हिस्सा मलेशिया की एयरएशिया बीएचडी के पास है। टाटा संस, एयरएशिया और सिंगापुर एयरलाइंस ने इस घटनाक्रम पर कमेंट करने से इनकार कर दिया। एक सूत्र ने कहा कि टाटा के हिस्से का खरीदार तलाशना आसान नहीं होगा क्योंकि एक तो एयरएशिया इंडिया का आकार छोटा है और इसका विस्तार काफी धीमी गति से हो रहा है, वहीं इससे भी अहम बात यह है कि सीबीआई एयरएशिया बीएचडी के सीईओ टोनी फर्नांडीस और एयरएशिया के दूसरे एग्जिक्यूटिव्स की कथित लॉबीइंग और दूसरे ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। सूत्र ने कहा, अपने खिलाफ इन मामलों के कारण टोनी के लिए भारत में बिजनेस करना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अपनी एयरलाइन के स्टेक की अच्छी वैल्यू मिले बिना वह यहां से नहीं जाएंगे। जिन विकल्पों पर विचार हो रहा है, उनमें से एक यह है कि विस्तारा के साथ जेट का विलय कर एक फुल सर्विस ब्रांड बनाया जाए और एसआईए की लो-कॉस्ट करियर स्कूट की तरह की एक कंपनी बनाई जाए, जिसने पिछले साल बजट करियर टाइगरएयर का अपने में विलय किया था।

गरीबी दूर करने के लिये उच्च आर्थिक वृद्धि जरूरी : जेटली

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। देश में गरीबी को कम करने और विकास का फायदा गरीबों तक पहुंचाने के लिये उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल करना जरूरी है। वित्त मंत्री अरुण जेतली ने बचत एवं खुदरा बैंकों के 25वें विश्व सम्मेलन को संबोधित करते हुये कहा कि विकास की बाट जोह रहा कोई समाज जीवन की गुणवत्ता में सुधार और विकास का फल गरीबों तक पहुंचाने के लिए अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता है।

जल्द दिखेगा आर्थिक वृद्धि का प्रभाव: वित्त मंत्री ने कहा कि भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए उच्च आर्थिक वृद्धि दर आवश्यक है। हम उच्च आर्थिक वृद्धि के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को गरीबी के गर्त से उबारना और उनका जीवन सुधारना चाहते हैं। लेकिन हम विकास और प्रगति का फायदा कुछ लोगों तक सीमित रह जाने और बाकी के उससे वंचित होने के जोखिम को लेकर भी सजग है। उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि का प्रभाव निश्चित रूप से दिखेगा लेकिन यह एक धीमी प्रक्रिया है और विकास की बाट जोह रहा समाज अनिश्चितकाल तक इसका इंतजार नहीं कर सकता है।

सरकार का उद्देश्य लोगों को बैंक से जोडऩा: जेतली ने नरेंद्र मोदी सरकार में चलाये गये वित्तीय समावेश अभियान पर बोलते हुये कहा कि हमारा उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से नहीं जुड़े लोगों को बैंक से जोडऩा, असुरक्षित लोगों को सुरक्षित करना और पूंजीहीन लोगों को वित्त पोषित करना और जिन क्षेत्रों में सेवाएं नहीं थी, वहां सेवाएं पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भारत में अब भी अधिकांश लोगों के पास बीमा और पेंशन की सुरक्षा नहीं है। जन धन योजना खातों के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के तहत सस्ती प्रीमियम पर लोगों के लिये बीमा की पेशकश की गयी है। कुल 14.1 करोड़ लोगों का दुर्घटना बीमा किया गया है जबकि 5.5 करोड़ लोगों को जीवन बीमा दिया गया है।

नयी कर प्रणाली ऑनलाइन: जेतली ने कहा कि अर्थव्यस्था को औपचारिक रूप देने के लिये सरकार ने बड़े मूल्य वाले नोट (500 और 1,000 रुपये) को बंद किया था। जिससे बड़ी मात्रा में बैंकिंग प्रणाली में नकदी आ गयी थी। सरकार ने नयी कर व्यवस्था माल एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली पेश की। इससे विभिन्न कर एक कर में समाहित हो गये हैं। उन्होंने कहा कि नयी कर प्रणाली पूरी तरह से ऑनलाइन है और बहुत सी गतिविधियों को औपचारिक प्रणाली में लेकर आई है।

इंटरनेट स्पीड में दूसरे नंबर पर रही ऐयरटेल

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। रिलायंस जियो अक्तूबर महीने में सबसे तेज 4जी आपरेटर रही है। माह के दौरान कंपनी की औसत व्यस्त समय की डाउनलोड रफ्तार 22.3 एमबीपीएस रही है। वहीं माह के दौरान आइडिया सेल्युलर की अपलोड रफ्तार सबसे ज्यादा रही है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

कितनी रही जियो की औसत स्पीड: ट्राई द्वारा माईस्पीड पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार आलोच्य अवधि में जियो की 4जी डाउनलोड गति का राष्ट्रीय औसत उसकी निकटतम प्रतिद्वंद्वी कंपनी भारती एयरटेल से दोगुना से अधिक रहा। इस दौरान एयरटेल की डाउनलोड रफ्तार 9.5 मेगाबिट्स प्रति सेकेंड (एमबीपीएस) दर्ज की गई।

तीन महीनों में कितनी रही डाउनलोडिंग रफ्तार: निजी क्षेत्र की इकाई ओपनसिग्नल द्वारा नवंबर के पहले सप्ताह में एक जून से 29 अगस्त, 2018 तक की अवधि के लिए जारी अध्ययन में 4जी डाउनलोड रफ्तार के मामले में एयरटेल को सबसे आगे बताया गया है। लेकिन ट्राई के पोर्टल पर प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार जून और अगस्त में भी जियो डाउनलोड रफ्तार के मामले में सबसे आगे थी। हालांकि, वोडाफोन और आइडिया ने अपने मोबाइल सेवा कारोबार का विलय कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी दोनों अलग-अलग ब्रांड नाम वोडाफोन और आइडिया के रूप में परिचालन कर रही हैं। ट्राई के विश्लेषण पोर्टल पर दोनों की रफ्तार भी अलग-अलग प्रकाशित की गई है।

इंटरनेट स्पीड में आइडिया-वोडाफोन कौन से स्थान पर: आइडिया और वोडाफोन ने अक्तूबर में क्रमश: 6.4 और 6.6 एमबीपीएस की डाउनलोड रफ्तार दर्ज की। हालांकि, 4जी अपलोड रफ्तार के मामले में 5.9 एमबीपीएस के साथ आइडिया सबसे आगे है। जब कोई व्यक्ति वीडियो देखता है, इंटरनेट चलाता है या ईमेल का इस्तेमाल करता है तो डाउनलोड रफ्तार महत्वपूर्ण होती है। वहीं जब कोई तस्वीर, वीडियो या अन्य फाइलें ई-मेल या सोशल मीडिया एप पर साझा करना चाहता है तो अपलोड रफ्तार महत्वपूर्ण होती है।

जियो ने किस-किस को पीछे छोड़ा: अक्तूबर में अपलोड रफ्तार के मामले में जियो ने वोडाफोन को पीछे छोड़ा है और 5.1 एमबीपीएस के साथ वह आइडिया के बाद दूसरे स्थान पर है। वोडाफोन नेटवर्क की औसत अपलोड रफ्तार 4.8 एमबीपीएस रही। एयरटेल के नेटवर्क पर यह 3.8 एमबीपीएस रही।

उबर को महंगी पड़ी बाइक की सवारी, कंपनी को हुआ 7 हजार करोड़ का घाटा

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। टैक्सी व अन्य सर्विस देने वाली कंपनी उबर को बाइक की सवारी करना इतना महंगा पड़ा कि कंपनी को 1 बिलियन डॉलर यानि कुल (7 हजार करोड़ रूपए) का नुक्सान उठाना पड़ा । कंपनी कुछ समय से बाइसाइकिल,स्कूटर और शिपमैंट क्षेत्र में निवेश करने पर जोर दे रही है जिस कारण कंपनी को इतना नुक्सान उठाना पड़ा है। उबर अभी तक तेजी से आगे बढ़ रही है क्योंकि इसकी राजस्व 1 वर्ष में 38 प्रतिशत बढ़कर 22.55 बिलियन डॉलर पहुंच गया है। उबर की बुकिंग 12.7 अरब डॉलर थी, जो पिछले तिमाही में 6

प्रतिशत और एक साल पहले 41 प्रतिशत थी। उबर कंपनी ने ग्रास बुकिंग से 12.7 बिलियन कमाए है। सब कुछ ड्राइवरों और डिलवरी करने वाले लोगों को कमीशन देने के बार कंपनी ने ये राशि जमा की है जो पिछली वर्ष से 34 प्रतिशत अधिक है। ये सब कंपनी ने अगले वर्ष शुरू होने वाले initial public offering से पहले हुआ है। 2016 के अंत में, उबर की बुकिंग वृद्धि 30 प्रतिशत तक पहुंच गई, और 2017 की शुरुआत में यह अभी भी दो अंकों की वृद्धि तिमाही से अधिक तिमाही में रही हालांकि, इस साल की शुरुआत में, बुकिंग की वृद्धि एकल अंकों में फिसल गई।

क्यों उठाना पड़ा नुक्सान: उबर कंपनी बाइसाइकिल, स्कूटर और माल ढोने वाले क्षेत्रों में निवेश करने के बारे में विस्तार से सोच रही है। उबर का मानना है कि 76 बिलियन की कीमत वाली इस कंपनी को और मजबूत बनाने के लिए इन क्षेत्रों में निवेश करना बहुत जरूरी है। ये काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

ग्राहकों से अलग ढंग से पेश आना चाहता है उबर: उबर अपने ग्राहकों के साथ अलग ढंग से पेश आने की सोच रहा है। उबर द्वारा अपने कारोबार को और विकसित करने के लिए उबर ईट्स, राईड पास एंड ड्रोन फूड जैसे प्रोजैकेट भी शुरू करने की सोच रहा है। उबर के सीईओ दारा खोसरोहाही कहते है कि अगर सैल्फ ड्राइविंग के प्रोजैक्ट को भी सफलता मिलती है तो ड्राइवर की जरूरत खत्म हो सकती है।

ओपी भट्ट ने यस बैंक के सीईओ की खोज समिति से दिया इस्तीफा

मुंबई 16 नवम्बर (ए)। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के पूर्व चेयरमैन ओ पी भट्ट ने निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) राणा कपूर के उत्तराधिकारी की खोज के लिए गठित समिति से इस्तीफा दे दिया है। बैंक ने बताया कि भट्ट खोज एवं चयन समिति में बाहरी विशेषज्ञ थे। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है।

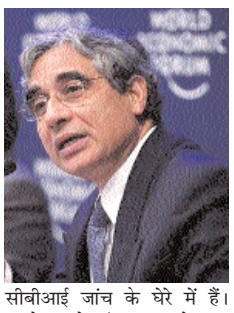

बैंक ने कहा कि कई संभावित 'हितों के टकराव' की वजह से भट्ट ने यह कदम उठाया हैं। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की बंद हो चुकी विमानन कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए कर्ज के मामले में भट्ट

सीबीआई जांच के घेरे में हैं। इससे पहले मंगलवार को यस बैंक के गैर कार्यकारी चेयरमैन अशोक चावला ने इस्तीफा दिया था। चावला का नाम एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र में आया था।

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से मोदी सरकार को मिलेगी राहत

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मोदी सरकार को बड़ी राहत दे सकती है। गत दिवस ये कीमतें 40 दिनों के सबसे निचले स्तर 65 डॉलर प्रति बैरल पर रहीं। बता दें कि 3 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 86 डॉलर प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आने के बाद माना जा रहा है कि इससे भारत सरकार को कई तरह के दबावों से मुक्ति मिलेगी।

अमरीका द्वारा ईरान पर लगाए गए हालिया प्रतिबंधों के बाद इसका प्रभाव तेल की कीमतों पर पडऩे की आशंकाएं जताई जा रही थीं। हालांकि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत सहित 8 देशों को इन प्रतिबंधों से अस्थायी छूट दे दी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। ऐसे में ईरान पर अमरीकी प्रतिबंध लागू होने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है। भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को देखते हुए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मोदी सरकार के लिए बड़ी राहत का संकेत मानी जा रही है। गौरतलब है कि भारत सरकार पैट्रोल-डीजल की कीमतों और डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार दबाव में चल रही है। ऐसे में कच्चे तेल की कम कीमतों से भारत का तेल आयात बिल कम होगा। इससे साथ ही भारत का करंट अकाऊंट डैफिसिट (कैड) भी कम होगा।

अक्तूबर में ईंधन मांग 4 प्रतिशत बढ़ी: कीमतें कम होने के बाद पैट्रोल एवं डीजल का उपभोग बढऩे से अक्तूबर महीने में देश में पैट्रोलियम ईंधन की मांग में 4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। पैट्रोलियम मंत्रालय के पैट्रोलियम नियोजन एवं विश्लेषण सैल के आंकड़ों के अनुसार इस साल अक्तूबर महीने में देश की ईंधन खपत 179.90 लाख टन रही जो पिछले साल अक्तूबर में 173 लाख टन थी। जब अगस्त महीने में वैश्विक बाजार में कच्चे तेल के भाव बढऩे और रुपए के कमजोर होने से ईंधन की कीमतें नरम पड़ रही थीं तब ईंधन मांग 0.3 प्रतिशत गिरकर 165 लाख टन पर आ गई थी। इसके बाद सितम्बर में भी जब कीमतें बढ़ रही थीं तब खपत एक प्रतिशत बढ़कर 165.10 लाख टन रही थी।

जोखिमों को देखते हुए भारत की रेटिंग को फिच ने रखा स्थिर, बीबीबी- पर बरकरार

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। रेटिंग एजेंसी फिच ने वृहद आर्थिक मोर्चे पर जोखिमों को देखते हुए भारत की रेटिंग को फिलहाल स्थिर परिदृश्य के साथ ''बीबीबी-'' बनाये रखने की बृहस्पतिवार को घोषणा की। फिच की यह रेटिंग निवेश कोटि में सबसे नीचे है। रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत के लिए वृहतआर्थिक परिदृश्य बड़ा जोखिम भरा है।

अगले दो वित्त वर्षों में घटेगी वृद्धि दर: फिच ने कहा कि भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि के 2017-18 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है लेकिन अगले दो वित्त वर्षों में वृद्धि दर घटेगी। रिर्पोट में कहा गया है कि वित्तीय स्थिति कठिन होने, वित्तीय क्षेत्र की बैलेंसशीट की कमजोरी और अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वृद्धि दर के घटने का जोखिम है।

इन वजहों से इकोनॉमी पर बना हुआ है दबाव: फिच ने कहा, 'मैक्रोइकोनॉमिक आउटलुक के प्रति जोखिम खासे ज्यादा हैं और बैंकिंग या शैडो बैंकिंग सेक्टर में समस्याओं के चलते क्रेडिट ग्रोथ में सुस्ती बनी हुई है। कमजोर फिस्कल पोजिशन के कारण भारत की सॉवरेन रेटिंग्स पर दबाव बना हुआ है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि सरकारी कर्ज जीडीपी का 70 फीसदी हो चुका है और जीएसटी सहित अन्य रेवेन्यू में कमी के चलते वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में जीडीपी की तुलना में 3.3 फीसदी का डेफिसिट टारगेट हासिल होना मुश्किल है।

इसके अलावा आम चुनावों के

फ्लिपकार्ट से बिन्नी बंसल के बाद अब मिंत्रा के सीईओ दे सकते हैं इस्तीफा

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। फ्लिपकार्ट के सीईओ बिन्नी बंसल के बाद अब मिंत्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और मुख्य वित्त अधिकारी अनंत नारायणन भी इस्तीफा दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के साथ नारायणन के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। बिन्नी बंसल के इस्तीफे के बाद नारायणन की रिपोर्टिंग कल्याण को हो गई है। बिन्नी ने यौन शोषण के आरोपों के चलते गुजरे मंगलवार को फ्लिपकार्ट के ग्रुप सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया था। नारायणन के साथ ही मिंत्रा के सीएफओ दीपंजन बसु भी कंपनी छोड़ सकते हैं।

अनंत और कल्याण के काम का तरीका अलग: अनंत नारायणन की लीडरशिप में पिछले साल मिंत्रा का घाटा 25 फीसदी कम हुआ। यह माना जा रहा है कि

अनंत नारायणन बिन्नी बंसल के करीबी थे। जबकि, नए ग्रुप सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति के कामकाज का तरीका उनसे अलग है। फ्लिपकार्ट का अपना फैशन वर्टिकल फ्लिपकार्ट फैशन भी है। इसे रिशि वासुदेव हेड करते हैं। फ्लिपकार्ट ने 2014 में मिंत्रा और 2016 में जबोंग को खरीद लिया था। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इन दोनों को फ्लिपकार्ट फैशन में मर्ज किया जा सकता है।

सहयोगी कंपनियों पर भी छंटनी की तलवार: फ्लिपकार्ट की सहयोगी कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों पर भी छंटनी की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि फ्लिपकार्ट अब जबोंग और मिंत्रा में काम कर रहे काफी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा देगी। सूत्रों के मुताबिक मिंत्रा में 500 और जबोंग में तकनीकि, वित्त और मानव संसाधन जैसे विभागों से कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा।

फेसबुक के 32% कर्मचारी कंपनी में अपने भविष्य को लेकर हुए निगेटिव

नई दिल्ली 16 नवम्बर (ए)। फेसबुक के लिए साल 2018 बेहद उतथ-पुथल वाला रहा। इस साल कंपनी कई बार डेटा लीक के विवाद में फंसी रही जिसके कारण कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों का मनोबल भी गिरता जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक के इंटरनल सर्वे के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया है कि कंपनी के सिर्फ 52 प्रतिशत कर्मचारी ही अब कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं और 32 प्रतिशत लोगों की फेसबुक को लेकर पॉजिटिव राय अब निगेटिव हो गई है। दरअसल, फेसबुक साल में दो बार कर्मचारियों की राय जानने के लिए इंटरनल सर्वे कराता है। ये सर्वे अप्रैल और अक्टूबर के महीने में कराया जाता है। हाल ही में हुए सर्वे में कर्मचारियों से 30 सवाल पूछे गए थे। सितंबर 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक, फेसबुक

में 33,606 कर्मचारी काम करते हैं।

70 प्रतिशत कर्मचारियों को फेसबुक में काम करने पर गर्व

इस सर्वे में 53 प्रतिशत कर्मचारियों ने माना कि फेसबुक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 19 प्रतिशत कम है। इसके अलावा 70 प्रतिशत कर्मचारियों ने ही कहा कि उन्हें फेसबुक में काम करने पर गर्व है जबकि पिछले साल 87 प्रतिशत लोगों ने इस बात को माना था। एक साल पहले हुए सर्वे में कर्मचारियों ने औसतन 4.3 साल तक फेसबुक में काम करने की इच्छा जाहिर की थी, जो अब कम होकर सिर्फ 3.9 साल हो गई है। 12 प्रतिशत लोगों ने फेसबुक में एक साल से भी कम काम करने की इच्छा जाहिर की।

पिछले साल 52 प्रतिशत कर्मचारी पॉजिटिव थे

एक साल पहले हुए सर्वे में फेसबुक के 84 प्रतिशत कर्मचारी कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव थे, जो अप्रैल में 67 प्रतिशत हो गए अब इनमें 32 प्रतिशत की गिरावट आ गई है और सिर्फ 52 प्रतिशत कर्मचारी ही कंपनी के भविष्य को लेकर पॉजिटिव हैं। ब्रिटिश फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने 8.7 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा चुराया, जिसका इस्तेमाल 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रम्प को जिताने के लिए किया गया था। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों से भी यूजर्स का पर्सनल डेटा शेयर किया गया। सिक्योरिटी फीचर में खामी के चलते 3 करोड़ यूजर्स का डेटा चोरी हुआ।

अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज रोकने के लिए भी फेसबुक ने कोई कदम नहीं उठाया। इन सबके अलावा मार्च में कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल सामने आने के बाद और मार्क जकरबर्ग से मतभेद होने की वजह से फेसबुक के कई बड़े अधिकारियों ने कंपनी छोड़ी, इससे भी कर्मचारियों का मनोबल गिरा।